शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 47 अंक-40 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 26-03 अक्तूबर 2022 मूल्य पांच रूपए

सत्ता में वापसी के लिए सिद्धांतों की आहुति देने के कगार पर पहुंची भाजपा

- चालीस टिकट बदले जाने की कवायद शुरू
- धूमल के चुनाव लड़ने का फैसला हाईकमान पर छोड़ने के संकेत
- नड्डा परिवार से बेटा या पत्नी के चुनाव लड़ने की संभावना

शिमला/शैल। भाजपा ने अभी तक विधानसभा चुनावों के लिये पार्टी के उम्मीदवारों की कोई सांकेतिक सूची तक जारी नहीं की है। जबकि कांग्रेस, माकपा और आप इस दिशा में भाजपा से बहुत आगे निकल चुके हैं। माना जा रहा है कि रणनीतिक तौर पर भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची अन्तिम दिन जारी करेगी। ताकि जिनके टिकट काट दिये जाते हैं उनके पास बगावत के लिए व्यवहारिक रूप से कोई समय न बचे। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि जो पार्टी केन्द्र और प्रदेश में दोनों जगह पार्टी की सरकारें होने के नाम पर सत्ता में वापसी के दावे कर रही है। वह इतना संभल कर क्यों चल रही है? उसे बगावत का खतरा क्यों महसूस हो रहा है? इस सवाल की पड़ताल करने के लिए 2017 के चुनावों से लेकर आज तक सरकार और पार्टी में घटी कुछ मुख्य घटनाओं का स्मरण करना आवश्यक हो जाता है। स्मरणीय है कि 2017 में भी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करने की रणनीति पर चली थी। लेकिन जब चुनाव प्रचार के दौरान यह फीडबैक मिला कि मुख्यमंत्री घोषित किये बिना जीत संभव नहीं है तब पीटरहॉफ की बैठक के बाद धूमल को मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ा। इस घोषणा का लाभ मिला और पार्टी को चुनावों में बहुमत हासिल हो गया। परन्तु इस जीत में धूमल और उनके आधा दर्जन कट्टर समर्थक चुनाव हार गये। यह हार कितनी प्रायोजित थी यह जंजैहली प्रकरण से लेकर मानव भारती विश्वविद्यालय प्रकरण में शान्ता कुमार, राजेन्द्र राणा और जयराम की संयुक्त सक्रियता तथा बाद में सुरेश भारद्वाज के ब्यान से पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है। इसी कारण से उस समय विधायकों का बहुमत धूमल के साथ होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उस समय जगत प्रकाश नड्डा ने भी मुख्यमंत्री बनने के लिये पूरे प्रयास किये थे और वह सफल नहीं हो पाये थे। यह पूरा प्रदेश जानता है।

इन परिस्थितियों में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री तो बन गये लेकिन आगे चलकर बतौर मुख्यमंत्री उनकी परफॉरमैन्स का जब यह परिणाम सामने आया कि भाजपा के पास डबल इंजन होते हुये भी चार में से दो नगर निगम हारने के बाद तीन विधानसभा के रूप और एक लोकसभा उपचुनाव हारने से शिमला नगर निगम का चुनाव करवाने तक का साहस नहीं कर पाये। इस स्थिति पर किसी भी हाईकमान का माथा टनकना स्वभाविक था। इससे प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें चलना शुरू हो गयी। कई मंत्रियों की छुट्टी करने और विभाग बदलने की चर्चाएं शुरू हो गयी। लेकिन यह चर्चाएं व्यवहारिक रूप नहीं ले पायी। क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा हिमाचल से ताल्लुक रखते थे। नड्डा धूमल शासनकाल में कैसे दिल्ली पहुंचे यह भी प्रदेश में सब जानते हैं। 2017 के चुनाव के बाद नड्डा ने फिर हिमाचल आने का मन बनाया तो जयराम ने इसे सफल नहीं होने दिया। लेकिन जब भी हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल दिल्ली में उठा तो जयराम का विकल्प नड्डा की जगह धूमल ही उभरा। परन्तु नड्डा के लिये यह दिल से स्वीकार्य नहीं हो पाया। इसलिये परिस्थितियों ने जयराम को ही कुर्सी पर बनाये रखा। लेकिन जयराम अपने को प्रमाणित नहीं कर पाये वह अपनो के स्वार्थों से ऐसे घिर गये कि शीर्ष प्रशासन पर उनकी पकड़ और समझ रेत की मूठी से आगे नहीं बढ़ पायी। जो मुख्यमंत्री लोकसेवा आयोग के लिये किये गये अध्यक्ष के अपने फैसले को अन्जाम न दे सके जिस मुख्यमंत्री के शीर्ष प्रशासन के आधा दर्जन अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच के लिये आय पी.एम.ओ. के फरमान को अमली शक्ल न दे पाये वह प्रधानमंत्री का कितना विश्वास पात्र बना रह सकता है। इसका अन्दाजा लगाना किसी भी राजनीति विश्लेषक के लिये कठिन नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री की प्रशासनिक पकड़ का ताजा उदाहरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में सामने आया है। वर्ष 2000 में स्व. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शुरू हुई इस योजना का अन्तिम चरण भी अब सितम्बर 2022 को समाप्त हो गया है। योजना का अन्तिम चरण 2019 में शुरू हुआ था। इस योजना में गांव को सड़कों से जोड़ना था। केंद्र में यह योजना ग्रामीण विकास विभाग देखता है। लेकिन हिमाचल में यह काम मुख्यमंत्री के लोक निर्माण विभाग के पास है। योजना समाप्त हो गयी है और इसके तहत बन रही 203 सड़के अभी तक अधूरी हैं। केन्द्र ने योजना की समय अवधि बढ़ाने का सरकार का आग्रह अस्वीकार कर दिया है। इनमें निवेशित हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया बेकार होने के कगार पर पहुंच गया है। यदि मुख्यमंत्री के प्रभार में चल रहे विभाग की यह स्थिति होगी तो अन्य विभागों का क्या हाल होगा? क्या ऐसी परफॉरमेन्स पर सत्ता में वापसी के दावे जमीनी हकीकत हो सकते हैं। इस परिदृश्य में ही सुजानपुर में राज्य सभा सांसद इन्दु गोस्वामी को धूमल को भारी बहुमत से विजय बनाने का आह्वान करते हुये नेतृत्व के प्रश्न पर भी कई संकेत छोड़ जाता है। जबकि आज भाजपा के विधायक किस तरह प्रशासन पर अपने नाजायज फैसले मनवाने के लिये प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं यह विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के वायरल वीडियो से सामने आ चुका है। उपाध्यक्ष केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से शिकायत करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनुराग ठाकुर तक की इस प्रकरण पर चुप्पी पार्टी और सरकार में फैली अराजकता का सीधा सन्देश दे रही है। इसी कारण से आज छः मंत्रियों सहित 30 विधायकों और 14 पूर्व विधायकों के टिकट काटने की चर्चा चल पडी है। इसी चर्चा के साथ नड्डा के बेटे या पत्नी तथा धूमल के चुनाव लड़ने का फैसला हाईकमान पर छोड़ा जा रहा है। निर्दलीयों और कांग्रेस से आये विधायकों तथा सुरेश चन्देल और हर्ष महाजन को शिमला की एक सीट से उम्मीदवार बनाने के लिये भाजपा अपने सिद्धांतों की आहुति देने के कगार पर आ पहुंची है।

राज्यपाल ने सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय नेरवा के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चौपाल उपमण्डल के बलसन में सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय नेरवा के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया। हिमाचल प्रदेश

के किसी भी राज्यपाल का नेरवा क्षेत्र का यह पहला दौरा है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा समिति द्वारा राज्य में शिक्षा का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संस्कारी और सभ्य नागरिक तैयार करना है क्योंकि इन्ही मूल्यों के कारण देश सुरक्षित रह सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा समिति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी विरासत को संजो कर ही विकास और प्रगति करता है। आर्लेकर ने कहा कि देश में शिक्षा के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। हिमाचल शिक्षा समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों को समिति के साथ सहयोग करना चाहिए और इन शिक्षण संस्थानों का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूल के लिए लगभग 2 बीघा जमीन दान देने के लिए स्थानीय निवासी मियां शवान सिंह की सराहना की।

इस अवसर पर हिमाचल शिक्षा समिति के प्रांत अध्यक्ष मोहन केप्टा ने कहा कि यह स्कूल 21 वर्ष से किराये के भवन में चल रहा था और आज इसका भवन बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने विद्यालय भवन के निर्माण में सहयोग करने वाले सभी लोगों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने विद्या मंदिर स्कूलों की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि इन स्कूलों का संचालन और रख-रखाव समाज द्वारा ही किया जाता है।

इस अवसर पर समाजसेवी कैप्टन संजय पराशर ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने स्कूल निर्माण के लिए 11 लाख रुपये की राशि दान की है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक बलबीर वर्मा, शिक्षा समिति के संगठन मंत्री ज्ञान चंद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शिमला के रिज में

महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म के आदर्शों को अपनाया था। स्वराज आंदोलन में उनका एक ही संदेश था और वह संदेश था ‘स्वदेशी, राम राज्य और ग्रामीण विकास’। उन्होंने भारतीय परंपराओं को सत्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने जीवन में अपनाया था।

इस अवसर पर राज्यपाल ने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसके बाद, राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सीटीओ चौक पर उनकी प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की।

राज्यपाल ने कहा कि देश की इन दोनों महान विभूतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया। आज देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर बनने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर देशभक्ति के गीत और भजन भी प्रस्तुत किए गए।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सक्षम गुड़िया बोर्ड की प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने एम्स संस्थान का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(एम्स) का दौरा किया।

इस अवसर पर एम्स के अध्यक्ष प्रमोद गर्ग ने राज्यपाल को संस्थान की गतिविधियों से अवगत करवाया।

राज्यपाल ने विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों को प्रदान की जाने वाली उच्च स्तरीय सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की।

संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिनेश वर्मा ने संस्थान की ढांचागत सुविधाओं के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाया।

इसके उपरान्त राज्यपाल की अध्यक्षता में बिलासपुर के उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में प्रधानमंत्री टी.बी मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत नि:क्षय मित्र कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों, संगठनों के प्रतिनिधियों और हितधारकों ने भाग लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान से हर व्यक्ति को जोड़ने पर बल दिया। आर्लेकर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने हम सभी को एक दिशा दिखाई है, इसलिए उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। हालांकि यह अभियान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से लागू किया जा रहा है, लेकिन यह एक सार्वजनिक अभियान होना चाहिए न कि सरकारी अभियान।’’ उन्होंने आग्रह किया कि राज्य में कोई भी संस्थान टीबी के मरीजों को गोद ले सकता है।

उपायुक्त पंकज राय ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि बिलासपुर जिले में टीबी की अधिसूचित दर 97 प्रतिशत है जबकि उपचार सूचकांक भी 97 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 392 टीबी रोगियों की पहचान की गई है, जिनमें से 70 प्रतिशत ने सामुदायिक सहयोग लेने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप प्रबंध निदेशक डॉ. गोपाल बैरी ने कहा कि 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में टीबी के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है और लगभग 45 प्रतिशत युवा इस बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य वर्ष 2023 तक हासिल कर लिया जाएगा।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, जिला रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने हमीरपुर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हमीरपुर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के साथ-साथ भावनात्मक जुड़ाव भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि सरकारें

अपने स्तर पर काम करती हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रयासों से सरकारी योजनाओं और अभियानों के क्रियान्वयन में तेजी आती है। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत बनाने के प्रधानमंत्री के आहवान को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को अपने-अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि इसके लिए वह स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने प्रदेश के हर जिले का दौरा किया है। उन्होंने लोगों से टीबी से ग्रस्त कम से कम एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने और उसे हरसंभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में हिमाचल में प्रति लाख जनसंख्या पर टीबी रोगियों की संख्या 191 थी। वर्ष 2021 में राज्य में टीबी के कुल 14492 मामले थे। इनमें से 2.6 प्रतिशत जनजातीय क्षेत्रों में, 74 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 23.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में थे। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर 2022 तक जिला हमीरपुर में टीबी के मरीजों की संख्या 442 है। इस अवसर पर राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को नि-क्षय मित्र पंजीकरण की संख्या में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दिशा में जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की।

इस अवसर पर उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने राज्यपाल का स्वागत किया और टीबी मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत जिला में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

बैठक में एडीएम जितेंद्र सांजटा, सहायक आयुक्त पवन कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. अग्निहोत्री, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने स्वच्छ भारत दिवस पर सैहब सोसायटी के फील्ड वर्कर्स को किया सम्मानित

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर ‘मैत्री सोसाइटी फॉर ऑल काइंड’

के माध्यम से सैहब सोसाइटी के फील्ड वर्कर्स को सम्मानित किया और उन्हें हीटर भी वितरित किए। इस अवसर पर मैत्री संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह संस्था अन्य संस्थाओं के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन गई है। उन्होंने कहा कि अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी इस तरह की गतिविधियों के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी, बाल विकास कार्य, स्वास्थ्य शिविर, अंगदान और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी संस्था की सराहना की।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

प्रधानमंत्री बनेंगे रथ यात्रा के साक्षी, हिमाचल के लिए होंगे ऐतिहासिक क्षण:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 5 अक्तूबर को कुल्लू दौरा प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। हिमाचल के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की ऐतिहासिक रथ यात्रा के साक्षी बनने जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिमाचल के प्रति स्नेह को दर्शाता है। आज कुल्लू के ढालपुर मैदान में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू आगमन से पहले प्रधानमंत्री बिलासपुर में एम्स सहित अरबों रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे तथा लुहणू मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जय राम ठाकुर ने बताया कि इसके पश्चात प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की ऐतिहासिक रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ यात्रा में भाग लेने हेतु सहमति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल की संस्कृति का सम्मान करते हैं और प्रदेश के प्रति उनका विशेष लगाव है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बिलासपुर में करीब 1471 करोड़ रुपये की लागत के एम्स तथा लगभग 140 करोड़ रुपये की लागत वाले देश के दूसरे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री करीब 350 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क तथा 1692 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले पिंजौर-नालागढ़ फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ी सौगात हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ढालपुर में रथ यात्रा के लिए तैयारियों के संबंध में जिला प्रशासन से फीडबैक लिया और उचित दिशा-निर्देश जारी किए।

उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग और अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न प्रबंधों से अवगत करवाया।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, एचपीएमसी के उपाध्यक्ष राम सिंह, एपीएमसी अध्यक्ष अमर ठाकुर, राज्य विपणन बोर्ड के सलाहकार रमेश शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष भीमसेन सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।

देश के शीर्ष संस्थानों में जगह बना रहा है टांडा मेडिकल कालेज:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान

महाविद्यालय टांडा देश के शीर्ष आयुर्विज्ञान संस्थानों में अपनी जगह बना रहा है। वह टांडा स्थित महाविद्यालय परिसर में केंद्रीय छात्र संघ द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम-'संस्कृति' में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में एक प्रसिद्ध पत्रिका द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस संस्थान की ओवरऑल रैंकिंग 35 से 25वें स्थान तक पहुंच गई थी और वर्तमान में यह 13वें स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार चिकित्सकों के 500 नए पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एमबीबीएस प्रशिक्षुओं का स्टाईपेंड 17,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 5 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उदार सहायता और डबल इंजन सरकार के कारण हिमाचल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 अक्तूबर को बिलासपुर में एम्स का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जो प्रदेश के लोगों के लिए यह एक और गौरवमयी अवसर होगा।

एमबीबीएस प्रशिक्षुओं से मानवता के प्रति अपनी सर्वश्रेष्ठ और पेशेवर सेवाएं सुनिश्चित करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों ने बहुत ही सराहनीय सेवाएं प्रदान की थीं। इनकी संयुक्त सेवाओं और आम लोगों की भागीदारी के कारण हिमाचल प्रदेश कोविड रोधी टीकाकरण में देश भर में प्रथम रहा।

सितम्बर माह में जीएसटी संग्रहण में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, युनूस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीएसटी संग्रहण में 28 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस वित्त वर्ष में सितम्बर माह के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में 18 प्रतिशत प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सितम्बर माह में 386 करोड़ रुपये जीएसटी संग्रहण किया गया है। उन्होंने कहा इस वित्त वर्ष के दौरान प्रथम छः माह में जीएसटी संग्रहण 2,641 करोड़ रुपये रहा है।

उन्होंने कहा कि यह वृद्धि करदाताओं में कर अदायगी सम्बन्धी अनुपालना में सुधार तथा विभाग द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रयासों तथा प्रवर्तन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से सम्भव हो पाई है।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत की वार्षिक संचयी वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभाग ने रिटर्न फाइलिंग में निरन्तर सुधार, रिटर्न की तीव्र छंटनी, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करना और मजबूत प्रवर्तन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है।

विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष में अपने रोड चौकिंग अभियान में छः लाख 70 हजार ई-वे बिल सत्यापित किए हैं। विभाग स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और टैक्स हाट कार्यक्रम के तहत समयबद्ध रूप से हितधारकों के मुद्दों का निवारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में हितधारकों के लिए 7 सितम्बर, 2022 को विभिन्न स्थानों पर कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में आम व्यापारियों, उद्यमियों, उद्योगपतियों और अन्य हितधारकों ने काफी उत्साह दिखाया तथा एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस कार्यक्रम को इण्डिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यूनिक रिकॉर्ड के तौर पर पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रमों से स्वैच्छिक अनुपालना में सुधार आने की सम्भावना है।

उन्होंने कहा कि विभाग टैक्स अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि तथा क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है। गत सात माह के दौरान 400 कर अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विभागीय पुनर्गठन की सैद्धान्तिक मंजूरी और प्रशिक्षित अधिकारियों के सशक्त प्रयासों से विभाग को राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

जाठियादेवी में प्लॉट निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपये के प्राक्कलन को मंजूरी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार शहरी विकास के लिए कृतसंकल्प है तथा हिमाचल प्रदेश आवास तथा शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) इस उद्देश्य

के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। यह बात शहरी विकास तथा आवास मंत्री और हिमुडा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने हिमुडा के निदेशकमण्डल की 51वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतरीन आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

बैठक के दौरान निदेशक मण्डल ने धर्मशाला में नई आवासीय कॉलोनी स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। यहां प्रथम चरण में 158 प्लॉटों का निर्माण करने के उपरान्त इच्छुक प्रार्थियों को आबंटित किया जाएगा। हिमुडा ने इन प्लॉटों के आबंटन के लिए 31 अक्तूबर, 2022 तक आवेदन आमंत्रित करने की तिथि निर्धारित की है। आवेदनों की छानबीन के उपरान्त 10 नवम्बर, 2022 को ड्रॉ निकाला जायेगा और उमीदवारों को आबंटित किये जाएंगे।

निदेशक मण्डल ने धर्मशाला कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए 127 करोड़ रुपये के प्राक्कलन की भी मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त शिमला में हवाई अड्डे के नजदीक जाठियादेवी में भी प्रथम चरण के प्लॉटों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये के प्राक्कलन की मंजूरी भी प्रदान की।

इसके आलावा बैठक के दौरान बद्दी, परवाणू, शिमला व रोहड़ू क्षेत्रों में व्यावसायिक सम्पत्तियां विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई जिसकी अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपये है। निदेशक मण्डल ने परवाणू में क्षतिग्रस्त उठाऊ पेयजल योजना की मुरम्मत के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की व इस कार्य को जल्दी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बोर्ड द्वारा हिमुडा के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए संशोधित वेतनमान व पेंशन की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

निदेशक मण्डल ने हिमुडा में लिपिक, स्टेनौ टाईपिस्ट, कनिष्ठ अभियन्ता सिविल व इलेक्ट्रीकल, कनिष्ठ प्रारूपकार सिविल, सहायक कंम्प्यूटर प्रोग्रामर व विधि सहायक के प्रारम्भिक भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा टेक्निशियन व चालक के भर्ती नियमों में छूट व वरिष्ठ आशुलिपिक के एक पद के लिए सेवा मानदंड में छूट की अनुमति प्रदान की।

बैठक में निदेशक मण्डल ने हिमुडा में लिपिक, स्टेनौ टाईपिस्ट, कनिष्ठ अभियन्ता सिविल व इलेक्ट्रीकल, जूनियर ऑफिस असिस्टैंट आई.टी., स्टैनो टाईपिस्ट, कनिष्ठ प्रारूपकार सिविल, सहायक कंम्प्यूटर प्रोग्रामर व विधि सहायक के 42 पदो को अनुबंध के आधार पर भरनें व सहायक अभियन्ता के तीन पदों को पदोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की गई। बोर्ड ने हिमुडा के वर्ष 2021-2022 के संशोधित बजट व 2022-2023 के बजट अनुमान के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक का संचालन हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव डॉ. राज कृष्ण पुर्थी ने किया। इस अवसर पर हिमुडा के गैर-अधिकारिक सदस्य अनुपाल चौहान तथा सुनील मनोचा, प्रधान सचिव आवास देवेश कुमार तथा निदेशक मण्डल के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने 150 पेटी अवैध शराब बरामद की

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त युनूस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने ऊना जिले में एक पिकअप जीप से अवैध रूप से ले

जायी जा रही देशी शराब की 150 पेटियां बरामद की हैं। विभाग की टीम ने पिकअप जीप को जब्त कर चालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

आयुक्त ने बताया कि विभाग को काफी समय से अवैध रूप से शराब के परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने अम्ब रोड से ऊना की तरफ जा रही है जीप से अवैध शराब बरामद की।

युनूस ने बताया कि विभाग प्रदेश में स्थित सभी खुदरा शराब की दुकानों, थोक विक्रेताओं की आबकारी अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण कर रहा है। यदि कोई भी लाइसेंसधारक संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि विभागीय टीमों द्वारा प्रदेश में नाका लगा कर वाहनों का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के परिवहन, वितरण, उत्पादन एवं उपभोग्य वस्तुओं के भंडारण पर शिकंजा कसने के लिए ट्रांसपोर्टर्स, ई-कॉमर्स, कूरियर सर्विसेज के गोदामों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।

धर्म हृदय का विषय है। कोई भी शारीरिक असुविधा किसी के अपने धर्म को छोड़ने का अधिकार नहीं कर सकती। .....महात्मा गाँधी

सम्पादकीय

अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के नाम पर महंगाई कब तक

आरबीआई ने मुद्रास्फीति दर निर्धारण पैनल के फैसले के बाद बैंकों को दिये जाने वाले कर्ज की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। रिजर्व बैंक को पिछले कुछ अरसे में ऐसा चौथी बार करना पड़ा है। आरबीआई का कहना है कि उसे ऐसा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के परिदृश्य में करना पड़ा है। बैंकों को दिये जाने वाले कर्ज की ब्याज दरें बढ़ाने का अर्थ है कि अभी महंगाई और बढ़ेगी यह दरें बढ़ाये जाने के साथ ही यह भी कहा गया कि प्राकृतिक गैस का रेट बढ़ गया है और इसका प्रभाव यह हुआ है कि सी एन जी ने अपने दामों में 40% की वृद्धि कर दी। आरबीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भविष्य में ऐसा कब तक चलेगा। यह दरें बढ़ने के साथ ही विकास दर का आकलन भी नीचे आ गया है। महंगाई बढ़ने के कारण ही केंद्र सरकार ने 80 करोड लोगों को दिये जाने वाले मुफ्त अनाज की समय सीमा भी इस वर्ष के अंत से आगे बढ़ाने में असमर्थता जाहिर कर दी है। इस वर्ष तक भी बढ़ौतरी हिमाचल और गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के कारण हो पायी है। अगले वर्ष 80 करोड़ लोगों को अनाज खरीदना भी कठिन हो जायेगा यह स्पष्ट है। जब महंगाई बढ़ती है तो उसी अनुपात में बेरोजगारी भी बढ़ती है यह सामान्य सिद्धांत है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का तर्क देकर आम आदमी को इस बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछने से रोका जा सकेगा? कितनी बार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का तर्क देकर महंगाई और बेरोजगारी परोसी जाती रहेगी? क्योंकि नोटबंदी से लेकर आज तक देश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती गयी है लेकिन सरकार की नीतियों पर सवाल नही उठने दिये गये। आज यह सामने आ चुका है कि 9 लाख करोड़ मूल्य के 2000 के नोट गायब हैं। परन्तु इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है इसका कोई जवाब नहीं आया है। 2014 के बाद से हर तरह के बैंक जमा पर ब्याज दरें क्यों कम होती गयी हैं? आज जो बैंक हर सेवा का शुल्क ग्राहक से वसूल रहे हैं तो फिर जमा पर ब्याज दरें कम करने की नौबत क्यों आयी? जीरो बैलेन्स के नाम पर खोले गये जनधन के खातों पर न्यूनतम बैलेन्स की शर्त लगाकर जुर्माना लगाने का फैसला क्यों लिया गया? आज जो न्यूनतम बैलेन्स के नाम पर आम आदमी का 500 और 1000 रुपए के रूप में हजारों करोड़ों का बैंकों और डाकघरों में उस पर क्या दिया जा रहा है? बड़े कर्जदारों का लाखों करोड बट्टे खाते में डाल दिया गया। नीरव मोदी जैसे कितने लोग बैंकों का हजारों करोड लेकर भाग गये हैं लेकिन उनको वापस लाने और उनसे वसूली के सारे प्रयास असफल क्यों होते जा रहे हैं? क्या यह लाखों करोड़ देश का इस तरह लूटने से बचा लिया जाता तो इससे आरबीआई को यह फैसले न लेने पड़ते।

आज सरकार को यह जवाब देना होगा कि 2022-23 के बजट में ग्रामीण विकास के आवंटन में 38% की कटौती क्यों की गयी थी? क्या इसी के कारण आज मनरेगा में कोई पैसा गांव में नहीं पहुंच पा रहा है। पीडीएस के बजट में भी भारी कटौती की गयी थी और उसी कारण से आज 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने का संकट आ रहा है। बजट में यह कटौती तो उस समय कर दी गयी थी जब रूस और यूक्रेन में युद्ध की कोई संभावनाएं तक नहीं थी। इसलिए आज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के परिदृश्य में सरकार की नीयत और नीति पर खुली बहस की आवश्यकता हो जाती है।

सच पूछिए तो पीएफआई मुसलमानों की रहनुमाई का भी हक नहीं रखता

गौतम चौधरी

अंततोगत्वा भारत सरकार को देश के सबसे खतरनाक इस्लामिक चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाना ही पड़ा। पटना की घटना के बाद से देश की सुरक्षा एजेंसिया बेहद सतर्क थी। उन्हें लगातार इनपुट मिल रहा था कि पीएफआई के गुर्गे पूरे देश में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने के फिराक में हैं। इसके कई प्रमाण सामने आते ही केन्द्र सरकार ने सख्त कदम उठाया और पीएफआई को पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया।

पीएफआई अपने आप को बेहद निहायत और शरीफ संगठन बताता है लेकिन उसके खतरनाक कारनामें लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हिसाबि विवाद मामले में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। बहुसंख्यक समुदाय के लोगों की बेरहमी से हत्या से लेकर कई गैरकानूनी कामों में पीएफआई की भूमिका संदिग्ध रही है। इन तामम्मा बारदातों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नाम जुड़े हैं। यह संगठन बेहद शातिराना तरीके से देश के अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम युवकों को चरमपंथ में दीक्षित कर, बहुसंख्यकों के बीच इस्लामोफोविया पैदा कर कर रहा था। इससे देश में अशांति फेलने की पूरी संभावना थी। इस बीच पीएफआई ने एक नया खेल प्रारंभ किया था, जो पूर्ण रूप से इस संगठन के स्वार्थ की तो पूर्ति करता है लेकिन इस्लामिक धार्मिक कायदों के एकदम उलट था। मसलन, भारतीय मुस्लिम समुदाय में बैत के सिद्धांत का प्रतिस्थापन।

इस्लामी शब्दावली में, बैत एक नेता के प्रति निष्ठा की शपथ है, जिसका पालन पैगंबर मुहम्मद ने किया था। ऐतिहासिक रूप से बैत एक प्रतिज्ञा थी, जो पैगंबर के समय में साथियों द्वारा स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं को अलग रखकर इस्लामी समाज की सुरक्षा और स्थिरता के लिए ली गई थी। धार्मिक रूप से, बैत केवल मुसलमानों के नेताओं को दिया जा सकता है और इसे निर्णय निर्माताओं यानी विद्वान, विशिष्ट पद वाले लोग द्वारा दिया जाना चाहिए। बैत का एक और पहलू यह है कि आम लोगों को खुद इस्लामिक नेताओं के प्रति निष्ठा रखने की जरूरत नहीं है और न ही उनके खिलाफ जाने या उनके खिलाफ विद्रोह करने की जरूरत है। इन पहलुओं को पूरा किए बिना बैत की मांग करने वाला कोई भी निश्चित रूप से इस्लामी सिद्धांतों व शिक्षाओं से परे होगा।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), भारत में स्थित एक कट्टरपंथी संगठन, जो पूरे भारत के राज्यों में अपनी हिंसक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, भारतीय मुसलमानों से बैत की मांग करने लगा था। इस कारण मुसलमानों के धार्मिक नेता भी पीएफआई के प्रति नकारात्मक भाव रखने लगे थे। कई इस्लामिक विद्वानों ने पीएफआई के इस कदम को इस्लामिक नजरिए के खिलाफ भी बताया था लेकिन पीएफआई को इस्लाम से क्या लेना देना उसे तो बस एक खास किस्म की राजनीति करनी थी और अपने सरपरस्तों को राजनीतिक व आर्थिक लाभ पहुंचाना था।

सबसे पहले, पीएफआई के नेता निश्चित रूप से मुसलमानों के नेता होने के योग्य नहीं हैं। वे राजनीति से प्रेरित हिंसक संगठन हैं जिनकी पहुंच मुठी भर भारतीय मुसलमानों के बीच है। उनके नेता खुद को रोल मॉडल के रूप में पेश करने के बजाय विभिन्न हिंसक घटनाओं व घोटालों में शामिल हैं। पीएफआई के अध्यक्ष ओएमए सलाम को वर्तमान में केरल राज्य सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि इसके युवा विंग के नेता पर आबादी के एक वर्ग के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए मुकदमा चल रहा है। कुछ अन्य नेता मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर लोगों की हत्या तक के कई मामलों के आरोपी हैं।

पैगम्बर के जीवन पर एक सरल नजर डालने से यह साफ हो जाता है की पीएफआई के नेता मुसलमानों के नेतृत्व के लायक बिलकुल नहीं हो सकते। दूसरी बात, बैत देने के लिए पीएफआई नेता निश्चित रूप से विद्वानों और सद्गुणी लोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं। पीएफआई के नेता लोगों को विद्वतापूर्ण सलाह देने के बजाय हमेशा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने, लोगों में दुश्मनी पैदा करने और विभाजनकारी राजनीति करने में लगे रहते हैं। तीसरी शर्त विशेष रूप से कहती है कि आम लोगों को खुद इस्लामिक नेताओं को बयान देने की जरूरत नहीं है। यदि पीएफआई नेता मुसलमानों के नेतृत्व का दावा कर रहे हैं, तो उन्हें पहले विद्वानों के पास बैत (जो अधिकार रखता है) लेने के लिए जाना चाहिए और निश्चित रूप से आम मुसलमानों के पास नहीं जाना चाहिए जो बैत देने से जुड़ी शर्तो से अनजान हैं। इसकी मान्यता के लिए तो कोई इस्लामिक धार्मिक विद्वान, या फिर ऐसा नेता जो दुनियाभर के मुसलमानों की धार्मिक रूप से सरपरस्थी कर रहा हो वहीं अधिकारिक ताकत रखता है।

यह किसी धर्म में होता है। आजकल हिन्दुओं में भी कई ऐसे धार्मिक नेता खड़े हो रहे हैं, जिन्हें पारंपरिक साधुओं ने कोई मान्यता नहीं प्रदान की है। इन नेताओं को हिन्दू परंपरा से कोई लेना-देना नहीं है। न ही ये गुरू-शिष्य परंपरा के वाहक हैं। आजकल ऐसे कई शंकराचार्य, त्रिडंडी स्वामी, हंस, परमहंस आदि घुम रहे हैं। यही नहीं ईसाई समुदाय में भी इस प्रकार के धार्मिक नेता खड़े हुए हैं, जिन्हें धार्मिक परंपरा और सिद्धांतों से कोई लेना-देना नहीं है। ये तमात अपारंपरिक नेता दुनिया भर में घूम रहे आवारा पूंजी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, जिनका एक मात्र काम समाज में वैमष्यता फैलाना है। पीएफआई भी ऐसा ही एक संगठन है, जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड के पैसे ने ताकत प्रदान कर रखी है।

विभिन्न समूहों के प्रति निष्ठा देने के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस्लामी विद्वान शेख सालिह अल-फौजान ने कहा कि बैत मांगने वाले विभिन्न समूह स्व-प्रेरित हैं और विभाजन के कारणों में से हैं। शेख फौजान का फतवा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आम मुसलमानों से वफादारी की मांग करने वाले पीएफआई नेता और कार्यकर्ता न केवल इस्लाम विरोधी हैं, बल्कि जन-विरोधी भी हैं। एक देश या एक राज्य में रहने वाले मुसलमानों को देश के एक नेता के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए कई प्रकार की बैत रखना जायज नहीं है। (अल-मुंतका मिन फतवा अल-शेख सालिह अल-फवजान, 1:367)

भारत जैसे देश में रहने वाले मुसलमानों को अपने नेता (भारत के प्रधानमंत्री) के प्रति निष्ठा होना लाजमी है। वफादारी की मांग करने वाले विचलित समूह न केवल मुसलमानों को अपने चुने हुए नेताओं को धोखा देने के लिए कह रहे हैं, बल्कि देश के कानून के खिलाफ जाने के लिए भी बाध्य कर रहे हैं। पीएफआई नेताओं का अधिकारियों के साथ टकराव का इतिहास रहा है, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पडता। परन्तु, हर आम मुसलमान को जो पीएफआई द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ऐसा करने के बाद उपर वाले के प्रकोप का तो सामना करना ही पड़ेगा।

चीते की तरह तेजी से दौड़ेगा भारत

वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री भारत सरकार

शिमला। भारत को अगले 25 साल में समृद्ध और विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। तीव्र, समान विकास के साथ देश में आमूलचूल बदलाव लाने का लक्ष्य है और इसे हासिल किया जाएगा।

वास्तव में, यह परिवर्तन आठ साल पहले शासन में मूलभूत बदलावों के साथ ही शुरू हो गया था, जिसने आम आदमी को सशक्त और विशेष होने का अहसास कराया है। इसके साथ ही भारत दुनिया में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभरा, जिसके साथ हर देश बड़ी उत्सुकता से जुड़ना चाहता है।

नई लॉजिस्टिक्स नीति भारत के गौरव को बढ़ाने की दिशा में नवीनतम पहल है। लॉजिस्टिक्स में 5 'आर' महत्वपूर्ण होते हैं। राइट यानी सही उत्पाद पाना, सही स्थिति में, सही जगह, सही समय पर और सही ग्राहक को मिलना।

नई नीति में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी 'आर' सही हों। यह छोटे किसान, एमएसएमई, बड़ी फैक्ट्रियों और आम आदमी के हित में होगा। यह अर्थव्यवस्था के इंजन को कुछ इस तरह से गति देगा कि करोड़ों नौकरियां पैदा होंगी, समृद्ध महानगरीय क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों के बीच असमानताओं को खत्म करने में मदद मिलेगी, माल और लोगों की आवाजाही में तेजी आएगी और दक्षता बढ़ने से भारी बचत होगी।

यह नीति लॉजिस्टिक्स खर्च को अनुमानित रूप से जीडीपी के 13-14 प्रतिशत से घटाकर इकाई अंक के स्तर पर ले आएगी। यह बचत बहुत बड़ी है। 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में पांच प्रतिशत-प्वाइंट की बचत 150 अरब डॉलर के लाभ के बराबर है, जो भारत के संपूर्ण आउटसोर्सिंग उद्योग के अनुमानित मूल्य के बराबर है।

इस उपहार से सबसे बड़ा लाभ छोटे किसानों और बड़ी संख्या में एमएसएमई को होगा क्योंकि कम मूल्य के सामानों का परिवहन खर्च अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है जबकि रत्नों और गहनों जैसे कीमती सामानों की खेप तो हवाई मार्ग से ले जाने पर भी लाभदायक हो सकती है।

परंपरागत रूप से, छोटे किसान अक्सर फलों और सब्जियों को औने-पौने भाव पर बेच देते हैं क्योंकि खराब होने वाली वस्तुओं में सड़न शुरू होने से पहले इसे खरीदार तक पहुंचना जरूरी होता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स के साथ, ऐसी चीजों को शीघ्र ही लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है जिससे इसे नए बाजार मिलेंगे।

बेहतर लॉजिस्टिक्स से आपूर्ति में काफी सुधार होगा और लागत में कमी आयेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कृषि उपज के खेत से थाली तक के सफर में, पूरा अर्थशास्त्र सुखद रूप से बदल सकता है। इससे किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा और खरीदार को सस्ता खाना मिल सकेगा।

प्रत्येक उपभोक्ता की संपूर्ण खरीदारी के संबंध में अलग-अलग स्तर पर भी ऐसा ही होगा क्योंकि जिस चीज का भी उत्पादन होता है, विनिर्माण या निर्माण होता है उसके मूल्य के कम या ज्यादा होने में लॉजिस्टिक्स खर्च एक महत्वपूर्ण घटक होता है।

नई लॉजिस्टिक्स नीति मोदी सरकार की दूसरी प्रमुख पहलों, विशेष रूप से पीएम गतिशक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करती है, यह परिवर्तनकारी पहल डिजिटल रूप से सक्षम प्रणालियों के साथ बुनियादी ढांचा निर्माण की योजना से लेकर कार्यान्वयन को बढ़ावा देती है। डिजिटल सिस्टम से साइलो खत्म होते हैं और डेटा का खजाना एवं कई परतों में जानकारी उपलब्ध हो पाती है। इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने वालों और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों को वन भूमि, रक्षा भूमि, बिजली लाइनों के साथ ही कई अन्य मसलों के बारे में पहले से ही डेटा उपलब्ध हो जाता है जिससे अचानक कुछ ऐसा सामने न आए कि परियोजनाओं में देरी हो।

पीएम गतिशक्ति और नई लॉजिस्टिक्स नीति भी प्रधानमंत्री मोदी के संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण का उदाहरण है, जो शासन में साइलो विभागों के बीच समन्वय का अभाव से छुटकारा दिलाता है।

उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण, कंटेनर के वापस आने के समय में सुधार, तेज एवं सुरक्षित रेलवे और समर्पित माल ढुलाई गलियारे जैसी पहलों के साथ ये नीतियां विश्वस्तरीय डिजिटल तकनीक के साथ विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करेंगी, जिससे विकसित देशों की तरह उत्पादकों, वितरकों और खुदरा ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा मिले।

ये नीतियां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन, निर्यात में वृद्धि, दुनिया के साथ व्यापारिक जुड़ाव बढ़ाने, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रमुख पहलों में योगदान करती हैं। इन सभी पहलों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है।

यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि जो भी देश समृद्ध हुए हैं वहां तेज आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए वैश्विक व्यापार और निर्यात प्रमुख साधन रहे हैं। भारत ने रत्न और आभूषण, चमड़ा और हस्तशिल्प जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए विकसित बाजारों के दरवाजे खोलने के लिए व्यापार समझौतों का उपयोग करने की रणनीति अपनाई है।

बेहतर लॉजिस्टिक्स से निर्यातकों को बहुत अधिक लाभ होता है क्योंकि उनका सामान ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएगा और खरीदारों को तेजी से एवं निश्चित समय में पहुंचाया जा सकता है।

जैसा, प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा में पाया कि निर्यातकों को माल ट्रैक और ट्रेस करने के लिए शिपिंग बिल नंबर, रेलवे कंसाइनमेंट नंबर, ई-वे बिल नंबर आदि रखने होते हैं। उन्हें कई अधिकारियों के पास भी जाना पड़ता है। उनकी मदद के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स नीति के तहत ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज या ई-लॉग्स नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सामने आने वाली किसी भी समस्या को हल करने में मदद करेगा।

मोदी सरकार के आठ शानदार वर्षों में भारत में लॉजिस्टिक्स में पहले से काफी सुधार हुआ है। कोविड महामारी के चरम पर होने के दौरान देश ने दवाएं, ऑक्सीजन और खाद्यान्न पहुंचाया। डिजिटल इंडिया जैसी दूरदर्शी पहलों ने भारत को महामारी के चरम पर होने के दौरान घर से काम करने की आवश्यकता के अनुकूल बनाने में मदद की।

बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स अब भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए जरूरी लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। निश्चित ही, नीति बनाने मात्र से यह काम नहीं हो सकता है लेकिन जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 'नीति+प्रदर्शन = प्रगति' हासिल होगी।

नई नीति की घोषणा उस दिन की गई जिस दिन चीते भारत की धरती पर लौट आए। पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाले जानवर के आगमन ने परिवहन के लिए एक बड़ा संदेश दिया। लॉजिस्टिक्स के लिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, 'मुझे उम्मीद है कि आप चीते की रफ्तार से माल पहुंचाएंगे।' शानदार ट्रैक रिकॉर्ड और प्रदर्शन के आधार पर भारत निश्चित रूप से एक विकसित देश बनने के लिए चीते की तरह आगे बढ़ेगा।

हजारों बालिकाओं को लाभान्वित करके 'बेटी है अनमोल' को किया सार्थक

शिमला। महिला एवं बाल सशक्तिकरण किसी भी देश व प्रदेश के समावेशी, समतुल्य और दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान प्रदेश सरकार के लिए भी यह सदा से प्राथमिकता रही है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया है। जबकि सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं जैसे बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, नारी सेवा सदन, गृहिणी सुविधा योजना तथा स्वावलंबन योजना आदि सुनिश्चित करती हैं कि राज्य में विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की बेटियों और महिलाओं को अनुकूल और सुरक्षित वातावरण प्राप्त होने के अलावा उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो। इस दिशा में सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं न केवल शुरू कीं, बल्कि इन योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता से कार्य भी किया है।

राज्य सरकार ने बच्चियों का सही लालन-पालन, उन्हें आरामदेह परिवेश, महिलाओं को सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त सुगम व विश्वसनीय वातावरण, लैंगिक समानता और बाल केन्द्रित कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रम तैयार करने और एकरूपता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निरंतर कार्य किया है। सरकार द्वारा चलाया गया 'नारी को नमन' कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक साकारात्मक पहल सिद्ध हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराये में 50 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जा रही है। इस योजना से निगम की बसों में प्रति दिन यात्रा करने वाली लगभग 1.25 लाख महिलाओं को राहत मिल रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार लगभग 60 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय करेगी।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना गरीब परिवारों और महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करने में कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हा और सिलेंडर प्रदान कर रही है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से दिसंबर 2019 में हिमाचल देश का पहला एलपीजी सक्षम और चूल्हा धुआंमुक्त राज्य बन पाया। पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा 134 करोड़ रुपये व्यय कर 3.35 लाख पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। अब सरकार इन महिलाओं को दो रिफिल की जगह तीन रिफिल निःशुल्क उपलब्ध करा रही है।

सरकार ने लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने, लड़की के विवाह की आयु को बढ़ाने तथा लड़कियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बेटी है अनमोल योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गत लगभग पांच वर्षों के दौरान 40.86 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 21 हजार बच्चियों को जन्म उपरान्त अनुदान देने के अलावा 1,16,490 लाभार्थियों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की गई। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मी दो बेटियों के बैंक या डाकघर में जन्म के पश्चात 21 हजार रुपये जमा कर दिये जाते हैं जोकि 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर लड़की द्वारा आहरित किये जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत भी 8255 महिलाओं व लड़कियों जिनके पिता जीवित नहीं हैं तथा किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हैं और आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, को विवाह हेतु अब तक लगभग 39.29 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। बी.पी.एल परिवारों से संबंधित लड़कियों को भी विवाह में मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत 31 हजार रुपये की धनराशि शगुन के रूप में दी जा रही है और अब तक 20.54 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग सात हजार बेटियों को लाभान्वित किया है। विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि

प्रदान की जा रही है। गत वर्षों में 448 विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए 2.24 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

विवाह ही नहीं, बल्कि सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं है, को भी उनके दो बच्चों को 18 वर्ष तक पालन पोषण के लिए मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना के तहत छः हजार रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना से अब तक 39.39 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 99,206 लड़कियों को लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा असहाय, निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए मशोबरा में नारी सेवा सदन भी संचालित किया जा रहा है। यहां पर आवासियों को निःशुल्क भोजन, आवास चिकित्सा संबंधी सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। सदन छोड़ने पर महिलाओं को 25 हजार रुपये की पुनर्वास सहायता दी जाती है। यदि कोई आवासी विवाह करती है तो उसे 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान 176 लाभार्थियों को 2.36 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और समय-समय पर इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कड़ी निगरानी के साथ फीडबैक हासिल कर योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जा रहा है। महिलाओं के उत्थान की दिशा में सरकार निरंतर गतिमान दिख रही है जो प्रदेश में महिला एवं बाल सशक्तिकरण के उज्ज्वल भविष्य, समावेशी समतुल्य और दीर्घकालिक विकास का संकेत है। सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों के साकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं और राज्य के हर वर्ग की बच्चियों व महिलाओं के लिए ये योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं।

सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों के लिये बनेगी नीति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। मंत्रिमण्डल ने पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से सम्बन्ध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार 'हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम' का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत 'हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी' की स्थापना की जाएगी। यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्ध-कुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी।

मंत्रिमंडल ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा पात्र खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रायोजित करने या संबंधित विभागों को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया, ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनुशंसा या अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम छह सप्ताह की अवधि के इंतजार के बाद पद भर दिए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के पटवार वृत्त बंगा को तहसील सैंज से हटाकर तहसील बंजार में शामिल करने का निर्णय लिया।

बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन एवं भरने के साथ मण्डी जिले के थाना जंजैहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन/प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया। इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

बैठक में सोलन जिले की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणु और संसारपुर टैरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणु से चलने वाली तथा हरियाणा के केवल एक किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टैरेस या तलवाड़ा से चलने वाली तथा पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम

(अपग्रेडेशन) 2014 में संशोधन को भी मंज़ूरी प्रदान की।

बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह में विज्ञान और वाणिज्य की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुक्कड़ में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में चम्बा जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला भंदार को स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यार में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया।

बैठक में सोलन जिला के राजकीय स्नातक महाविद्यालय ममलीग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने तथा आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रतवाड़ी, दभोटा, राजपुरा एवं डोली में वाणिज्य कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नंड एवं भाटियां में विज्ञान तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोयला पनेड़, रेड़ू एवं गुल्लरवाला में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं प्रारंभ करने तथा आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया।

बैठक में सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय तुझार को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला के रिकांग पिओ में स्टाफ के आवश्यक पदों सहित सहायक जिला पर्यटन विकास अधिकारी का पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबंध एवं दैनिक वेतनभोगी आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 40 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकों/वैज्ञानिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने कैडर समीक्षा समिति की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की कुल कैडर क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की कमरऊ तहसील में 11 पटवार वृतों को पुनर्गठित कर सात नए पटवार वृत सृजित करने और इनके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र गाहलियां को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की निहरी तहसील के जनोह में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकीपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की बंजार तहसील के स्वास्थ्य उपकेंद्र दयोरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिंडल ने कुल्लू जिला की बंजार तहसील के स्वास्थ्य उपकेंद्र बठाड़ को आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत रानीताल में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी जिला के बालीचौकी क्षेत्र के चोड़ी बटवाड़ा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में सिरमौर जिला के कोटला बांगी (राजगढ़) में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की चच्योट तहसील की ग्राम पंचायत गुडार में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी जिला की थुनाग तहसील के केयोली में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिला की सुलह विधानसभा क्षेत्र में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मण्डी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागाचनोगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालीचौकी को 50 बिस्तर की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की जोगिन्द्रनगर तहसील की ग्राम पंचायत गुम्मा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में कांगड़ा जिला के स्वास्थ्य उपकेन्द्र राजनाल को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में मण्डी जिला की बालीचौकी तहसील के धंडाली में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंडबाड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्तरोन्नत करने के साथ ही आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के होल्टा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में ऊना जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला गगोह को राजकीय केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के गोथला, कांढी एवं जैशला में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कुल्लू जिला के शिक्षा खंड कुल्लू के अंतर्गत बलरगा में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय पांवटा साहिब, सतौन व कफोटा का पुनर्गठन कर खोदोवाला में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत सोमगार्ड के धनोट गांव में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में मण्डी जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला केल्टी और थुनारीगढ़ को राजकीय केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के कुमारहटी गांव (मनाली क्षेत्र) में नया पशु औषधालय खोलने के साथ ही आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने का भी निर्णय लिया।

बैठक में मण्डी जिला के थुनाग के शिहाल गांव में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने बैजनाथ तहसील पटवार वृत्त बीड़ का पुनर्गठन कर चौगान में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में मण्डी जिला की चच्योट तहसील के तहत छपराहन में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया।

बैठक में परवाणू शहरी और परवाणू ग्रामीण में दो नए पटवार वृत्त बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने सीजीएसटी मंडल एवं सीजीएसटी रेंज मण्डी के लिए कार्यालय भवन एवं आवासीय आवास निर्माण के लिए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नाम बिक्री आधार पर 2,17,89,414 रुपये शुल्क के साथ नियमित स्वामित्व में भूमि हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सोलन जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोघों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत करने व आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ मण्डी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटिड नाम से संयुक्त उद्यम की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की। इसमें प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत पूंजीगत हिस्सेदारी तथा और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की 49 प्रतिशत पूंजीगत हिस्सेदारी होगी।

बैठक में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ मण्डी जिले के पंजाई एवं शिल्लीबागी में उद्यान प्रसार केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने खौली-द्वितीय और 126 मेगावाट की छतड़ू पन बिजली परियोजनाओं को अपफ्रंट प्रीमियम की दरों पर बीओओटी आधार पर नियम एवं शर्तों के अनुसार निजी क्षेत्र को आवंटित करने का निर्णय लिया।

बैठक में शिमला जिले के शोघी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाओं की स्थापना के लिए 1000 वर्ग मीटर की सीमा शर्त में ढील देते हुए 500 वर्ग मीटर करने को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ मण्डी जिले के बालीचौकी में ओक टसर रेशम उत्पादन प्रभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों और इनके समकक्ष कैडर के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से यूजीसी के तर्ज पर संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भरठियां के राजकीय उच्च विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा सिरमौर जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला पनयाली को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में मण्डी जिला की प्राथमिक पाठशाला भलवाड़ और तुंगाधार, बिलासपुर जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला शोरा ब्यूंस, साई खारसी और पिपल घाट, कांगड़ा जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बड़ुखर, सिरमौर जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला भूपपुर, कुल्लू जिला की प्राथमिक पाठशाला मनिहार, कोइशुधर, खद्याणा, रामनगर, रास्कट और डोभी, शिमला जिला की राजकीय प्राथमिक स्कूल दावन को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने के साथ आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड द्वारा संचालित किए जा रहे सभी विद्यालयों को स्टाफ सहित शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान की गई। इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्हें इस संबंध में आगामी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया।

बैठक में कुल्लू जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला रंबी तथा शरई तथा जिला बिलासपुर की राजकीय प्राथमिक पाठशाला संदयार को स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

शिमला रोपवे परियोजना से कम किराए और समय में होगी आवाजाही: सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर के लिए लगभग 15 किलोमीटर लम्बी रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल गयी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना कि खास बात यह रहेगी कि शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय की भी बचत होगी और कम किराए में आवाजाही हो सकेगी। परियोजना के हिसाब से 10 किलोमीटर तक (रोपवे के हिसाब से दूरी) के सफर के लिए 50 रूपये किराया देना होगा।

उन्होंने कहा कि सही मायने में यह परियोजना जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होगी क्योंकि इससे समय की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार रोपवे लगाने की बातें हुई हैं लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार ने अनुमानित 1546.40 करोड़ रुपये की इस परियोजना को मंजूरी दी है।

यह रोपवे परियोजना तारादेवी से शुरू होगी और इसमें स्मार्ट पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर का संयोजन मौजूदा परिवहन नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह एक कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट होगा।

शहरी विकास मंत्री के समक्ष इस परियोजना के सम्बन्ध में रैपिड एंड रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन ने प्रस्तुति भी दी। मंत्री ने शिमला से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम किराए में स्थानीय लोगों को सुविधा देने के लिए यह एक बेहतरीन योजना है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल स्थानीय लोगों के आवागमन बल्कि शिमला में पर्यटन की दृष्टि से भी लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यातायात के नए माध्यम तलाशने एवं कार्यान्वित करने के लिए इस कॉर्पोरेशन की स्थापना की है। जल्द ही इस परियोजना से सम्बंधित वांछित औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शिमला के लिए यह न केवल एक बड़ी सौगात है बल्कि एक व्यावहारिक योजना भी है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 14.69 किलोमीटर की नेटवर्क लंबाई के साथ 15 बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग स्टेशन होंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना गाड़ियों पर निर्भरता को काफी हद तक कम करेगी और ट्रैफिक जाम व पर्यावरण को होने वाले नुकसान और समय की बर्बादी जैसी समस्याओं का भी समाधान होगा।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला में शहरी परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए यह एकमात्र व्यवहारिक समाधान है क्योंकि भौगोलिक और भू-तकनीकी सीमाओं के कारण बी.आर.टी.एस, मोनोरेल, मैट्रो का निर्माण यहां नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि औपचारिकताएं पूरी होते ही इस परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा और इसके निर्माण के लिए 5 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला की संकरी सड़कों को चौड़ा किया गया है। इसके अलावा सड़कों के एक ओर पैदल चलने के लिए 17 किलोमीटर के लगभग रास्तों का निर्माण किया गया है। शहर के विकासनगर में हाल ही में लिफ्ट तथा फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर फुटओवर ब्रिज तथा लिफ्ट का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा एस्केलेटर भी स्थापित किये जा रहे हैं और ढली में डबल लेन सुरंग लगभग बनकर तैयार है।

पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र साबित होगा 'देव लोक': जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मनाली के निकट बड़ाग्रां बिहाल में सार्वजनिक निजी भागेदारी के अन्तर्गत 46 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पारम्परिक कला एवं शिल्प केन्द्र का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनाली विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और एशियन डेवल्पमेंट बैंक की परियोजना पारम्परिक कला एवं शिल्प केन्द्र 'देव लोक' यहां आने वाले कला प्रेमियों और पर्यटकों के लिए उत्कृष्ट स्थल साबित होगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश न केवल प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि पर्वतारोहण, रॉक क्लाइबिंग, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए भी यह आदर्श स्थल है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को अपने उत्पाद के प्रोत्साहन, प्रदर्शन और बाजार उपलब्ध करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि 22 एकड़ में फैली यह परियोजना साहसिक पर्यटन प्रेमियों के लिए आकर्षण का केन्द्र साबित होगी।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि 'देव लोक' इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आर्कषण होगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की समृद्ध और विविध इतिहास के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना में स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दीपा साही का आभार व्यक्त किया।

प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और देव लोक के प्रोमोटर दीपा साही और केतन मेहता ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित तथा संरक्षित करने में मील पत्थर साबित होगा।

उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग, पुलिस अधीक्षक गुरूदेव शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

पारिस्थितिकीय रूप से संवदेनशील क्षेत्रों की वहन क्षमता के आकलन के लिए समिति का गठन

शिमला/शैल। एनजीटी के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के पारिस्थितिक संवदेनशील क्षेत्रों (ईको-सेंसिटिव जोन) की कैरिंग कैपेसिटी असैसमेंट यानि वहन क्षमता के आकलन के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इसमें पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वन, शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों के अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, एचएफआरआई शिमला, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, जीबी पंत संस्थान कुल्लू, वाडिया हिमालयन भू-गर्भ संस्थान देहरादून और अन्य संस्थानों के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) प्रबोध सक्सेना ने इस समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के पारिस्थितिकीय रूप से संवदेनशील क्षेत्रों की वहन क्षमता के आकलन के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान प्रबोध सक्सेना ने वन विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के अधिसूचित पारिस्थितिक संवदेनशील क्षेत्रों की सूची और इनके संबंध में अन्य आवश्यक जानकारियां अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इन क्षेत्रों की वहन क्षमता के आकलन में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के अलावा आर्थिक, सामाजिक, ईको टूरिज्म, जनजातीय, वन्य जीवन, आपदा प्रबंधन और अन्य पहलुओं को भी शामिल करके एक समग्र एवं विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि प्रथम चरण में पायलट आधार पर प्रदेश के 4-5 क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, जीबी पंत संस्थान कुल्लू, वाडिया हिमालयन भू-गर्भ संस्थान देहरादून और अन्य संस्थानों की मदद ली जाएगी। इस संबंध में त्वरित कदम उठाने के लिए बैठक में एक उप समिति के गठन का निर्णय भी लिया गया।

इस अवसर पर पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक ललित जैन ने पारिस्थितिक संवदेनशील क्षेत्रों की वहन क्षमता के आकलन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई विभागों और संस्थानों ने अपने-अपने स्तर पर भी प्रदेश के कुछ पारिस्थितिक संवदेनशील क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किए हैं और इनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार की हैं। इनके आंकड़े भी वहन क्षमता आकलन रिपोर्ट में समाहित किए जा सकते हैं। इसलिए सभी संबंधित विभाग और संस्थान ये रिपोर्ट्स एवं सुझाव उप समिति के साथ साझा करें।

बैठक में अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, जीबी पंत संस्थान कुल्लू और वाडिया हिमालयन भू-गर्भ संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों ने भी वर्चुअल माध्यम से भाग लेकर अपने सुझाव रखे।

प्रदेश में बार-बार चोरी की घटनाओं में संलिप्त हैं 461 अपराधी

शिमला/शैल। प्रदेश में बार-बार चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों का पता लगाने व उनकी शिनाख्त करने के लिये हिमाचल पुलिस द्वारा पिछले दस वर्षो के अपराधिक रिकार्ड का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से 461 ऐसे अपराधियों का पता लगाया गया है जो चोरी व गृह भेदन के अपराधों में एक से अधिक बार संलिप्त रहे थे। इन अपराधियों में सबसे अधिक जिला शिमला में 110, सोलन में 79, बददी में 72, सिरमौर में 59, कांगडा में 38, मण्डी में 33, बिलासपुर में-26, ऊना में 19, जिला चम्बा में-11, किन्नौर में-11 व लाहौल एवं स्पिति में-3 है। अपराधिक रिकार्ड से यह भी पाया गया है कि उपरोक्त 461 अपराधियों में से 58 ऐसे अपराधी भी है जो पांच व पांच से ज्यादा चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहे थे। इन 58 अपराधियों में से 41 अपराधी हिमाचल प्रदेश के निवासी है व 17 अन्य राज्यों हरियाणा-5, बिहार-1, उत्तर प्रदेश-3, दिल्ली व पंजाब के 04-04 के निवासी है। पुलिस विभाग द्वारा उपरोक्त अपराधियों की गतिविधियों पर कडी निगरानी रखी जा रही है तथा वर्तमान में जो अपराधी जमानत पर है उन की जमानत का रदद करवाने के लिये सम्बन्धित न्यायालयों से अनुरोध किया जा रहा है ताकि वे पुनः चारी की वारदात को अन्जाम न दे सके। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 75 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अपराधियों को वर्धित दण्ड देने की संस्तुति भी की जायेगी।

पेयजल गुणवत्ता में अव्वल रहा हिमाचल गांधी जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे पुरस्कृत

शिमला/शैल। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हिमाचल प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश अब पेयजल गुणवत्ता में भी देश भर में प्रथम नंबर पर आया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि गांधी जयंती एवं स्वच्छ भारत दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जल जीवन मिशन में हिमाचल प्रदेश ने लगातार उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष भी नल कार्यशीलता के वृहद सर्वेक्षण के दौरान हिमाचल प्रदेश को पुनः पेयजल सेवा वितरण गुणवत्ता में देश भर में प्रथम आंका गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी प्रकार के वृहद सर्वेक्षण में जल गुणवत्ता और नल कार्यशीलता में प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया था।

जल शक्ति मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से लगातार भरपूर वित्तीय सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने इस वर्ष प्रदेश को 1344.94 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया है। इसके अन्तर्गत केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को 336.23 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी कर दी है। इसे मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार अभी तक जल जीवन मिशन के लिए कुल 3820.61 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवा चुकी है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट कार्यो को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को तीन वर्षो के दौरान 1028.43 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से पहाड़ी प्रदेश पर सदा अपनी उदार दृष्टि रखी है तथा जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए कई बार प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है।

जल शक्ति मंत्री ने बताया कि मिशन के तहत हिमाचल के चार जिलों के 21 खंडों की 2551 पंचायतों के 15,300 गांवों के सभी घरों में नल लगाए जा चुके हैं। अभी तक प्रदेश में लगभग 96 प्रतिशत घरों को कार्यशील नल प्रदान किए जा चुके हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मिशन के तहत नल कनेक्शन लगाने के साथ-साथ प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में बड़ी पेयजल योजनाएं बनाई जा रही हैं तथा पुरानी योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की सभी 63 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता दिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जल गुणवत्ता की जांच में पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रयोगशालाओं को न्यूनतम दरों पर जन मानस के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ प्रत्येक गांव को फील्ड टैस्ट किट प्रदान किए गए हैं और इन किटों के माध्यम से हर गांव की पांच महिलाओं को पेयजल की जांच का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक 45191 ग्रामीण महिलाओं को पेयजल जांच का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या कांग्रेसियों के भाजपा में आने से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे समाप्त हो जाएंगे

- विधायक अनिरुद्ध के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही भाजपा
- क्या हर्ष महाजन पर अपने ही आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों को भाजपा वापस लेगी
- हर्ष महाजन की गाड़ी का पंजीकरण और इन्श्योरैन्स खरीद से पहले ही नोटबंदी में कैसे संभव हुआ

शिमला/शैल। हिमाचल में जब तीन विधानसभा तथा एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिये उपचुनाव हुये थे और भाजपा की जयराम सरकार यह चारों उपचुनाव हार गयी तब इसके लिये मुख्यमंत्री ने महंगाई को जिम्मेदार ठहराया था। अब सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार और भाजपा नेता यह प्रचार कर रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा तथा भाजपा सत्ता में वापसी करेगी। ऐसा प्रचार तथा दावे करके भाजपा नेता अपने स्वभाविक राजनीतिक धर्म का पालन कर रहे हैं। क्योंकि चुनावों से पहले ऐसे दावे करना उसकी जिम्मेदारी है। जबकि कड़वा सच यह है कि अभी आर बी आई को बैंकों के दिये जाने वाले कर्ज की ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी हैं। यह दरें बढ़ाने का स्वभाविक परिणाम होगा कि आने वाले दिनों में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। जिसका प्रभाव हर घर और रसोई पर पड़ता है और व्यवहारिक रूप से सभी को समझ आता है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का फैसला पिछला बजट बनाते हुए ही ले लिया गया था जब गांवों से जुड़ी हर चीज के बजट में भारी–भरकम कटौतीयां कर दी गयी थी। यह कटौतीयां इसलिए की गयी थी क्योंकि आम आदमी की सुविधायें सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। इसलिए तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अहम सेवाएं भी पी.पी.पी. मोड पर प्राइवेट सैक्टर को देने का फैसला ले लिया गया है। आने वाली स्थितियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी अपनी मांगे बनाने के लिये हड़ताल का रुख करना पड़ रहा गया है। यह सारे प्रभाव चुनाव से पहले कुछ ही दिनों में आम आदमी को व्यवहारिक रूप से सामना करने पड़ेंगे यह तय है।

सरकार भी इन खतरों के प्रति सचेत है इसलिए सीबीआई, ईडी और आयकर जैसी जांच एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। यू.पी. विधानसभा चुनाव में यह पूरे देश ने देख लिया है कि जब भाजपा से जुड़ा एक जैन आयकर और ई.डी. की जांच में फंस जाता है तो कैसे उसके लिए सारा तर्क बदल दिया जाता है। लेकिन जब सपा से जुड़ा दूसरा जैन ई.डी. के निशाने पर आ गया तो फिर तर्क बदल गये। ऐसे दर्जनों मामले हैं जो जांच एजैन्सियों के राजनीतिक उपयोग का सच बयां करते हैं। हिमाचल में ही कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने तो सीधे मुख्यमंत्री पर उन पर भाजपा में शामिल होने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। इस आरोप का जवाब मुख्यमंत्री की ओर से न आकर सुरेश भारद्वाज की ओर से यह कहना कि लोग अपनी इच्छा से भाजपा में आ रहे हैं एक कमजोर प्रतिक्रिया है। बेरोजगारों में आज हिमाचल देश के टॉप छः राज्यों में शामिल है यह भारत सरकार की रिपोर्ट में दर्ज है। क्या आज कोई हिमाचल में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होना चाहेगा?

अभी जो लोग निर्दलीय या कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुये हैं वह राजनीति के साथ विजनैस से भी जुड़े हुये हैं। राजनेता को आयकर तथा ई. डी. जैसी एजैन्सियां कभी कहीं भी परेशान कर सकती हैं यह संदेश आम आदमी में नीचे तक जा चुका है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में गये पूर्व मन्त्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्षता के कारण भाजपा के आरोप पत्र में उनका नाम प्रमुखता से छपा हुआ है। भाजपा अपने ही आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों का क्या जवाब देगी इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। नोटबन्दी के दौरान देशभर में पुराने नोटों को नये नोटों में बदलने में

प्रदेश के सहकारी बैंकों का स्थान सबसे ऊपर रहा है। भाजपा ही इस पर एक समय सवाल उठा चुकी है। इसी नोटबन्दी के दौरान हर्ष महाजन 80 लाख की गाड़ी खरीद चुके हैं। इस गाड़ी का पंजीकरण और इन्श्योरेंस खरीदने से बहुत पहले हो चुका है। नूरपुर में हुआ यह पंजीकरण खरीद से पहले ही किन नियमों में संभव हुआ है भाजपा में ही इस पर एक समय सवाल उठ चुके हैं। चर्चा है कि यह सवाल अब फिर उठने जा रहा था। शायद इन सवालों से बचने के लिये ही हर्ष महाजन भाजपा में जाने के लिये बाध्य हुये हैं अन्यथा जो नेता एक दशक से भी ज्यादा समय से चुनावी राजनीति से विदा ले चुका हो उसकी चुनावी प्रासंगिकता आज कितनी शेष रह चुकी होगी। इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा नेता कुछ लोगों को राजनीतिक गाली देने से ज्यादा क्या योगदान दे पायेगा यह अपने में ही अब सवाल बनता जा रहा है। वैसे राजनीति में सिद्धांतों और स्वच्छता का आवरण ओढ़े रखने वाली भाजपा कांग्रेस से गये हुये कितने लोगों को टिकट दे पाती है इस पर सबकी निगाहें लगी गयी हैं।

भाजपा के भ्रामक प्रचार को क्यों चुनौती नहीं दे पा रहा है कांग्रेस नेतृत्व

शिमला/शैल। कांग्रेस के दो कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी छोड़ भाजपा में चले गये हैं। विधायक लखविन्दर राणा और पवन काजल भी भाजपा में शामिल हो गये हैं। तीन बार हमीरपुर से भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश चन्देल भी भाजपा में वापसी कर गये हैं। कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने वाले सभी नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक पर वही रश्मि आरोप दोहराये हैं जो भाजपा का केन्द्र से लेकर राज्य नेतृत्व अब तक लगाता आ रहा है। इनमें से कितने नेता ई.डी. और आयकर विभाग की दबिश से डरकर भाजपा में गये हैं यह सब आने वाले दिनों में सामने आ जायेगा लेकिन इन नेताओं के जाने से सही में कांग्रेस को कितना नुकसान होता है यह इस पर निर्भर करेगा कि जाने वाले कितने लोगों को भाजपा टिकट देकर चुनाव लड़वाती है और वह जीत भी जाते हैं। लेकिन इस जाने से भाजपा तन्त्र नौमिनेशन फाइल होने की अन्तिम दिन तक कई नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने की अफवाहें फैलाने के एजेंडे को अंजाम दे सकता है। इसका परिणाम भी उस समय सामने आ गया जब स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह ब्यान छप गया कि यदि कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह भी भाजपा में आना चाहे तो उनका स्वागत है। बल्कि जब मुख्यमंत्री का यह ब्यान छपा तब एक वीडियो भी जारी हुआ जिसमें किसी भाजपा नेता राणा की प्रतिभा सिंह के साथ मीटिंग होने तक का जिक्र हुआ कांग्रेस की ओर से न तो मुख्यमंत्री के ब्यान का और न ही इस वीडियो का कोई कड़ा जवाब आया। बल्कि यह जवाब न आने से और कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसी अफवाहों पर विराम लगवाना पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। आज अफवाहों और ज्योतिषी आकलनों को मनोवैज्ञानिक हमले की संज्ञा दी जाती है जिसे काऊन्टर करना आवश्यक हो जाता है। कांग्रेस नेतृत्व इस प्रचार का जवाब देने में असफल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय कांग्रेस में स्व. वीरभद्र सिंह के बाद नेतृत्व का सवाल स्वभाविक रूप से खड़ा है। क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कॉल सिंह भी 2017 का चुनाव हारने के बाद नेतृत्व के पहले दावेदार नहीं रह जाते हैं। इस समय चुनाव न हारने के मानक पर आशा कुमारी और मुकेश अग्निहोत्री तथा हर्षवर्धन चौहान रह जाते हैं। ठाकुर रामलाल और सुखविन्दर सिंह सुक्खू के नाम भी चुनाव हारने का तमगा चिपक चुका है। लेकिन जहां मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने को प्रमाणित कर दिया है वहीं पर मुकेश के बाद सुक्खू का बतौर अध्यक्ष रहा कार्यकाल भी पार्टी के लिये एक बड़ा योगदान रहा है जबकि वह स्व. वीरभद्र सिंह के साथ लगातार टकराव में रहे हैं। इस परिदृश्य में आज भाजपा के भ्रामक प्रचार को चुनौती देने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से प्रतिभा सिंह, आशा कुमारी, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री तथा हर्षवर्धन चौहान की बन जाती है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व भाजपा के प्रचार को सक्षम रूप से चुनौती नहीं दे पा रहा है। बल्कि इन सभी नेताओं को उनके ही चुनाव क्षेत्रों में बांध कर रखने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इस समय भाजपा जिला शिमला में सबसे ज्यादा कमजोर है भाजपा पर यह दबाव और पुख्ता करने के लिए यदि प्रतिभा सिंह शिमला से विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना पर काम करती हैं तो शिमला के अतिरिक्त पूरे प्रदेश में वीरभद्र सिंह के समर्थकों को न केवल सक्रिय होने का अवसर मिलता है बल्कि उनको एक राजनीतिक आका भी मिल जाता है। संयोग से भाजपा में धूमल के अतिरिक्त प्रदेश स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को आका नहीं मिल पाया है। क्योंकि जयराम एक वर्ग विशेष से बाहर ही नहीं निकल पाये हैं।